

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 नवम्बर, 1997

संख्या 16/25/97- पूर्वा - भारत सरकार, उद्योग विभाग (औद्योगिक विकास विभाग) प्रैस नोट संख्या 17/10/60/83 एल0 पी0, दिनांक 10 अक्टूबर 1984 के पैरा 1 के खंड (i)के अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित 20 प्रकार को उच्च प्रदूषण वाली बड़ी तथा मध्यम औद्योगिक इकाईयों के लिए पर्यावरणात्मक दृष्टिकोण से स्थल को उपायुक्ता के लिए अनुमोदन देने के लिए पर्यावरण विभाग को समक्ष राज्य प्राधिकरण के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात :-

1. प्राईमरी मैटालर्निकल प्रोड्यूसिंग उद्योग जैसे जिंक, लैड, कोवर, एलूमिनियम तथा स्टील
2. पेपर पहल तथा न्यूजप्रिंट
3. पैस्टीसाइडज़ / इनसैक्टीसाइडज़
4. रिफाइनरिज़
5. फटिलाइजरस
6. पेंटस
7. डाईज़
8. लैबर टेनिंग
9. राशन
10. सोडियम /पोटोशियम साईनाइट
11. बेसिक ड्रगज
12. फाउंडरी
13. स्टीरेज बैटरीज (लैड एसिड टाइप)
14. एसिड / अलकालीन

15. प्लारिटकस
16. रबड.-सिनथैटिक
- 17.सीमेंट
18. एसराबैरटीज
19. फरमनटेशन इंडस्ट्रीज
20. इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग

हरियाणा के राज्यपाल आगे पाधिरिक दृष्टिकोण से उपरोक्त बताए गए प्रवचनों में पड़ने वाली औद्योगिक इकाईयों के स्थल निवासी के लिए इसको निर्दिष्ट प्रस्तावों के बर्खात्मक निरीक्षण,मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति गठित करते है :-

1.	निदेशक पर्यावरण, हरियाणा	अध्यक्ष
2.	भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, हरियाणा	सदस्य
4.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा, हरियाणा	सदस्य
5.	प्रधान मुख्य वन पाल, वन विभाग, हरियाणा	सदस्य
6.	निदेशक, नगर तथा आयोजन विभाग,हरियाणा	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा	सदस्य
8.	तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग विभाग, हरियाणा	सदस्य
9.	पर्यावरण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, रानीपुर, हरिद्वार के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	विद्युत वस्तु विशेषज्ञ (समबद्ध विभाग / एजेंसी से)	सदस्य
11.	संयुक्त निदेशक,पर्यावरण विभाग. हरियाणा	सदस्य सचिव

एम0 एल0 तायल0,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

पर्यावरण विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT DEPARTMENT
Notification

The 21st November-1997

No. 16/25/197-Envo-III.- In pursuance of clause (i) of para 1 of the Government of India Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Press Note No. 17/10/60/83 –LP, dated the 10th December, 1984, the Governor of Haryana hereby declares the Department of Environment is competent State Authority to accord approval for suitability of site from environmental angle for following 20 types of highly polluting large and medium industrial units, namely:-

1. Primary metallurgical producing, industries viz, zinc, lead, copper, aluminium and steel.
2. Paper Pulp and Newsprint.
3. Pesticides / Insecticides
4. Refineries
5. Fertilizers
6. Paints
7. Dyes
8. Leather Tanning
9. Rayon
10. Sodium / Potassium Cyanide
11. Basic drugs
12. Foundry
13. Storage Batteries (lead acid type)
14. Acids / Alkalies

15. Plastics
16. Rubber Synthetic
17. Cement
18. Asbestos
19. Fermentation industry
20. Electro-plating industry

The Governor of Haryana further constitutes a Technical Committee consisting of following members for detailed examination, evaluation of the proposals referred to if for site clearance relating to the industrial units falling in the afore stated categories from environment angle :-

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Director, Environment, Haryana | Chairman |
| 2. | Representative of Ministry of Environment and Forests, Government of India | Member |
| 3. | Engineer-in-Chief, PWD, Public Health Branch, Haryana | Member |
| 4. | Engineer-in-Chief, PWD, Irrigation Branch, Haryana | Member |
| 5. | Principal-Chief-Conservator of Forests, Haryana | Member |
| 6. | Director, Town and Country Planning, Haryana | Member |
| 7. | Member Secretary, Pollution Control Board, Haryana | Member |
| 8. | Technical Expert, Industrial Department, Haryana | Member |
| 9. | Representative of Pollution Control Research Institute, Ranipur, Hardwar | Member |

10. Subject-Matter-Specialist (from concerned Member
Department / Agency).
11. Joint Director, Environment Department, Member- Secretary
Haryana

M.L. TAYAL,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana
Environment Department.